

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या - 63/2013/धौलपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या-1014/2009/धौलपुर)

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, डूंगरपुर.(अपीलार्थी) अप्रार्थी.

बनाम

मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज, धौलपुर.(प्रत्यर्थी) प्रार्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस. के. जैन, अधिकृत प्रतिनिधिप्रार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक

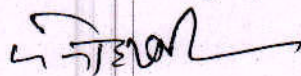
.....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15/10/2015

निर्णय

1. यह परिशोधन प्रार्थना-पत्र प्रार्थी व्यवहारी मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज, धौलपुर द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1014/2009/धौलपुर में एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2013 में संशोधन हेतु राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 37 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 व 100 तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, डूंगरपुर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 26.7.2008 को वाहन संख्या आर.जे.27/जी-1741 को चैक किये जाने पर वाहन में अहमदाबाद से धौलपुर के लिये '10 टन बटर' परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल से सम्बन्धित बिल्टी संख्या 15161 दिनांक 26.7.2008, मैसर्स खरगांधी डेयश्री प्रोडक्ट प्रा0 लि0 अहमदाबाद का बिल नं0 R 025 दिनांक 26.7.2008 तथा घोषणा-पत्र वैट-47 संख्या 1145980 प्रस्तुत किये गये। उक्त दस्तावेजों की जांच करने पर घोषणा-पत्र वैट-47 पूर्णतया रिक्त पाया गया। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा माल परिवहन में वैट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) की पालना नहीं होना मानते हुए वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आदेश दिनांक 01.08.2008 पारित करते हुए शास्ति रूपये 3,67,200/- का आरोपण किया गया। प्रार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा)

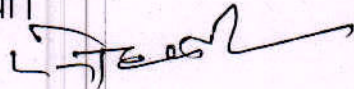


लगातार.....2

के आदेश दिनांक 30.3.2009 से स्वीकार किये जाने के विरुद्ध विभाग द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 1014/2009/धौलपुर प्रस्तुत की गयी। माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त गुलजग इण्डस्ट्रीज के निर्णय 18 टैक्स अपडेट 321 के आलोक में आदेश दिनांक 03.07.2013 पारित करते हुए राजस्व की अपील स्वीकार की गयी।

3. प्रार्थी व्यवहारी द्वारा माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ के उक्त आदेश दिनांक 03.07.2013 को विधिविरुद्ध बताते हुए अधिनियम की धारा 37 सपटित वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधित किये जाने हेतु यह परिशोधन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. बहस के दौरान प्रार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा सुनवाई दिनांक 04.08.2008 के लिये नोटिस जारी किया गया था, किन्तु बिना किसी आधार के दिनांक 01.04.2008 को ही शास्ति आदेश पारित कर दिया गया। प्रार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के नोटिस की पालना में नया घोषणा-पत्र वैट-47 संख्या 1145979 प्रस्तुत कर दिया गया था। वक्त चैकिंग प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में माल के प्रेषक-प्रेषिति का पूर्ण विवरण अंकित था, सक्षम अधिकारी द्वारा कोई जांच किये बगैर शास्ति का आरोपण किया गया था। घोषणा-पत्र रिक्त रहने का तर्कसंगत कारण सक्षम अधिकारी को बता दिया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त समस्त आधारों पर विचार करने के उपरान्त सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त करते हुए प्रार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी थी। माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2001) 124 एस.टी.सी. 611 मैसर्स डी.पी.मैटल्स; माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2013 (36) टैक्स अपडेट 37 मैसर्स हीरामणि फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ़ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन नं0 212/2012 मैसर्स वीडियोकोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2014 का हवाला देते हुए प्रार्थी का परिशोधन प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने तथा माननीय एकलपीठ का आदेश दिनांक 03.07.2013 अपास्त किये जाने का निवेदन किया।



5. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर बोर्ड की एकलपीठ के आदेश दिनांक 03.07.2013 का समर्थन करते हुए कथन किया कि सचेतन मस्तिष्क से पारित निर्णय को अधिनियम की धारा 37 अथवा वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। उक्त धारा के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि ही संशोधनीय है। माननीय एकलपीठ द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों का समुचित विश्लेषण करने के उपरान्त राजस्व की अपील स्वीकार की गई है, जिसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः प्रार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना-पत्र बलहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253] का हवाला देते हुए प्रार्थी का संशोधन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।
7. प्रकरण में माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2013 का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

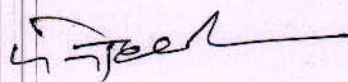
“उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में जांच अधिकारी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, डूंगरपुर को दिनांक 26.7.2008 सांय 4:30 बजे उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर, उदयपुर से दूरभाष पर निर्देश मिलने पर कि वाहन संख्या आर.जे.27/जी-1741 अहमदाबाद से 10 टन बटर भरकर बिच्छीवाड़ा में मैसर्स बागेश्री डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा० लि० के यहां खाली होने हेतु करापवंचन की नीयत से आ रहा है। जांच किये जाने पर रात्रि 2:00 बजे उक्त वाहन में बटर परिवहनित करना पाया गया तथा वाहन चालक/माल प्रभारी ने माल बिच्छीवाड़ा के लिये लेकर आना बताते हुए बयान दिये तथा दस्तावेजों में बिल्टी संख्या 15161 दिनांक 26.7.2008 मैसर्स श्री नाकोड़ा लोजिस्टिक्स हैदराबाद अहमदाबाद से धौलपुर, मैसर्स खरगांधी डेयरी प्रोडक्ट प्रा० लि० अहमदाबाद का बिल नं० R 025 दिनांक 26.7.2008 बटर कीमतन रूपये 12,24,000/-, प्रेषिति खरीददार मैसर्स भोले बाबा फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड धौलपुर तथा वैट-47 फॉर्म नं० 1145980 पूर्णतया खाली प्रस्तुत किये, जिसके लिफाफे पर मोबाईल नं० 9928720300 अंकित मिले। जांच अधिकारी ने उक्त मोबाईल नं० पर सम्पर्क करने पर बटर घी के ब्रोकर का कार्य



लगातार.....4

करने वाले श्री अमित टेलर बिच्छीवाड़ा का पाया गया। इस प्रकार सशक्त अधिकारी ने करापवंचन की नीयत से माल पपरिवहन करने तथा घोषणा पत्र वैट-47 पूर्णतया खाली पाये जाने के कारण वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन पाते हुए वाहन चालक तथा माल आयातक मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज को नोटिस जारी किया। जिसके प्रत्युत्तर में माल परिवहनकर्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रमेश जैन ने माल धौलपुर प्रेषिति को ही प्रेषित करना बताते हुए खाली घोषणा पत्र का कारण अहमदाबाद में बम धमाकों की वजह से बताते हुए एक अन्य घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 1145979 माल मूल्य में ओवरराईटिंग व कटिंग किया हुआ प्रस्तुत किया। सशक्त अधिकारी ने घोषणा पत्र खाली होने के कारण को इसलिए अमान्य किया कि अहमदाबाद में बम ब्लास्ट सांय 6:30 बजे के बाद हुए थे, जबकि माल 4:30 बजे ही रवाना होने की शिकायत उपायुक्त (प्रशासन) को प्राप्त हो चुकी थी। बाद में प्रस्तुत घोषणा पत्र से वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) की पालना नहीं होना मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित आदेश दिनांक 1.8.2008 से शास्ति रूपये 3,67,200/- आरोपित की, जिसे अपीलीय अधिकारी ने सशक्त अधिकारी द्वारा बिना परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर विचार करना मानते हुए, बिना अग्रिम जांच, दस्तावेजों को गलत या कूटरचित प्रमाणित किये बिना संदेह के आधार पर व नोटिस की पालना में नया घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करने के आधार पर शास्ति अपास्त की है।

प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक का मुख्य तर्क घोषणा पत्र वैट-47 खाली पाये जाने का कारण अहमदाबाद में बम ब्लास्ट की स्थिति में वाहन चालक जल्दी में अहमदाबाद छोड़कर रवाना हो गया था, बताया। लेकिन इस कारण के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। यह सही हो सकता है कि दिनांक 26.7.2008 को सांय 6:30 बजे बम ब्लास्ट हुए थे, लेकिन सशक्त अधिकारी को मिली सूचना अनुसार वाहन 4:30 बजे ही रवाना हो चुका था। यह सूचना उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर उदयपुर को शिकायतकर्ता द्वारा दी गई थी, जिसकी उपायुक्त (प्रशासन) ने 4:30 बजे जांच हेतु निर्देश दूरभाष पर दिये थे। माल प्रभारी वाहन चालक साहिन खां द्वारा भी अहमदाबाद में बम ब्लास्ट की घटना होना बयानों में नहीं बताया था। मैसर्स श्री नाकोड़ा लोजिस्टिक्स द्वारा 28.7.2008 को सशक्त अधिकारी को लिखे पत्र में भी नोटिस के जवाब में अहमदाबाद में बम ब्लास्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इन आधारों पर घोषणा पत्र खाली होने का कारण अहमदाबाद में बम ब्लास्ट नहीं होकर



लगातार.....5

शिकायत अनुसार माल बिच्छीवाड़ा में खाली करने की नियत से परिवहन करना उचित प्रतीत होता है। रिक्त घोषणा पत्र से माल परिवहन करना वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का स्पष्ट उल्लंघन है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने गुलजग इण्डस्ट्रीज प्रकरण (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक का दूसरा तर्क जवाब के साथ घोषणा पत्र प्रस्तुत करना प्रावधान की पालना होना बताया है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2001) 124 एस.टी.सी. 611 से समर्थित बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध दूसरे घोषणा पत्र में माल की कीमत शब्दों व अंकों में काटकर भरा गया है। इसके अतिरिक्त जवाब के साथ दूसरा घोषणा पत्र प्रस्तुत करना, जबकि परिवहनित माल के साथ उपलब्ध घोषणा पत्र पूर्णतया खाली पाया जाना, माननीय उच्चतम न्यायालय के गुलजग इण्डस्ट्रीज के निर्णय 18 टैक्स अपडेट 321 के तथ्यों से पूर्णतया सदृश है। इसलिए बाद में प्रस्तुत घोषणा पत्र जो कि परिवहनित माल के साथ दस्तावेजों में अस्तित्व में नहीं था, प्रस्तुत करने से वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) की पालना नहीं मानी जा सकती है।

उक्त विवेचनानुसार सशक्त अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण में कोई विधिक भूल नहीं की गई थी, फिर भी अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों का सही परिप्रेक्ष्य में निर्वचन नहीं कर शास्ति को अपास्त कर अपील आदेश पारित किया है। अतः अपील आदेश दिनांक 30.3.2009 को एतद्वारा अपास्त किया जाता है तथा सशक्त अधिकारी के आदेश दिनांक 01.08.2008 को बहाल (Restore) किया जाकर राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है।”

8. राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 37 निम्न प्रकार है :-

Section 37- Rectification of a mistake.- (Rajasthan Sales Tax Act, 1994)

(1) With a view to rectifying any mistake **apparent from the record**, any officer appointed or any authority constituted under the Act may rectify suo motu or otherwise any order passed by him.

Explanation.- A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgement of the Supreme court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

(2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.



- (3) Where an application under sub-section (1) is presented to the assessing authority, appellate authority or Tax Board and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.
- (4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of order sought to be rectified.
- (5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.

9. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 निम्न प्रकार है :-

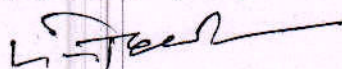
Section 33. Rectification of a mistake. – (Rajasthan Value Added Tax Act, 2003)

- (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under this Act may rectify *suo motu* or otherwise any order passed by him.

Explanation. – A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgment of the Supreme Court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

- (2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.
- (3) Where an application under sub-section (1) is presented to the assessing authority and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.
- (4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of the order sought to be rectified.
- (5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.

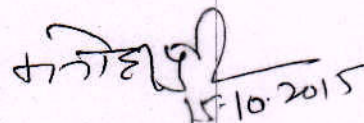
10. इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253] में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 37/33 के अधीन निहित शक्तियों



लगातार.....7

का प्रयोग अभिलेख से प्रकट भूल की स्थिति में ही किया जा सकता है। समस्त अभिलेख का पुनर्मूल्यांकन इस धारा के अधीन अनुज्ञेय नहीं है। निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

- "18. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a re appreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22.01.2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinised it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records.
19. Thus, the order passed by the Taxation Board on 22.1.2009 as also the impugned order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored."
11. इसी प्रकार का मत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 42 टैक्स अपडेट पार्ट-3 पेज 103 सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अलवर बनाम पी.एन.सी. कंस्ट्रक्शन, धौलपुर में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 में प्रतिपादित किया गया है।
12. उपरोक्त विवेचना के पश्चात प्रार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना-पत्र में प्रस्तुत किये गये तर्कों में माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय को गलत निर्वचित किया हुआ बताने के कारण प्रकरण में अभिलेख से प्रकट तथ्य या विधि की भूल होना नहीं पाया जाता है। निर्णय का पुनरावलोकन धारा 37/33 की परिधि व विषयक्षेत्र में नहीं आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2011) 29 टैक्स अपडेट 253, जो पैरा संख्या 10 में वर्णित है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय 42 टैक्स अपडेट पार्ट-3 पेज 103, जो पैरा संख्या 11 में वर्णित है, के आलोक में प्रार्थी व्यवहारी का परिशोधन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है।
13. निर्णय सुनाया गया।


15.10.2015
(मनोहर पुरी)
सदस्य